>

Title : The Minister of Civil Aviation made a statement correcting the reply given on 28.03.2012 to Starred Question No. 217 by Shri Asaduddin Owaisi and Shri Nama Nageswara Rao, MPs regarding Aircraft under EU Emission Trading.

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI AJIT SINGH): Sir, I beg to lay on the Table of the House a statement (Hindi version only) correcting the reply given on 28.03.2012 to Starred Question No. 217 regarding Aircraft under EU Emission Trading.

(क) जी, हां ।

(ख) जनवरी, 2012 से ईयू के किसी भी हवाई अड्डे पर आगमन या प्रस्थान करने वाली सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से होने वाला उत्सर्जन ईयू-ईटीएस के दायरे में आएगा । हालांकि इससे हवाई किराए पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव उल्लेखनीय होने की आशा है किन्तु इसका अनुमान नहीं लगाया जा रहा हैं चूंकि सरकार के इस योजना का विरोध करने के रूख का देखते हुए कोई भी भारतीय विमान वाहक इस वर्ष उत्सर्जनों के संबंध में अपेक्षित परीक्षण नहीं कर रहा है । अतः होने वाले प्रभाव का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी हां । भारत सहित कई देशों ने विभिन्न मंचों पर उपरोक्त योजना पर अपनी आपत्ति जताई है । इस देशों में चीन, अमेरिका, ब्राजील, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, जापान, रूस्, सऊदी अरब, नाइजीरिया आदि सम्मिलित है ।

(घ) और (ड.) 1 जनवरी 2012 से ईयू के किसी हवाई अड्डे के लिए भारतीय अतंरराष्ट्रीय उड़ान का एकपक्षीय तरीके से शामिल किए जाने की वजह से नागर विमानन मंत्रालय ने नई दिल्ली में 29-30 सितबंर 2011 को आईसीऐओ कांउसिल के गैर-ईयू सदस्यों तथा अन्य गैर-ईयू सदस्य देशों की एक अंतरराष्ट्रीय बैठक की मेजवानी की थी जिसमें ईयू-ईटीएस का विरोध करने वाला एक संयुक्त घोषणापत्र अंगीकृत किया गया । तत्पश्चात् भारत ने अपने नेतृत्व में एक कार्यपत्र संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया, जिसे इकाओ काउंसिल द्वारा अंगीकृत कर लिया गया ।

अंतरराष्ट्रीय विरोध और आईसीएओ के संकल्प के बावजूद, वार्ता के लंबित रहते इस स्कीम को वापस लेने या निलम्बित करने के प्रति ईयू की निरंतर अनिच्छा के कारण 21-22 फरवरी 2012 को मास्को में एक अन्य फालो-अप बैठक आयोजित हुई, जिसमें 32 देशों ने भाग लिया । उपस्थित देशों ने ईयू-ईटीएस पर मास्को घोषणापत्र अंगीकृत किया, जिसमें इस बार सभी सरकारों के पास प्रति कार्रवाईयों के रूप में विभिन्न जवाबी उपाय उपलब्ध हैं । मास्को घोषणापत्र पर ईयू की प्रतिक्रिया के आधार पर भारत सहित इस घोषणा पत्र के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा और उन अन्य देशों द्वारा भी जो मास्को घोषणापत्र से जुड़ने के इच्छुक हैं, समुचित उपाय किए जाएंगे।

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I would like to ask the hon. Minister that in relation to EU ETS, China in February has barred its airlines from participating in the scheme and suspended the purchase of nearly 14 billion worth of planes from European airlines. In our Indian market, Airbus has 73 per cent share. It has orders of 250 planes. Your own Minister in the Cabinet, Environment Minister has called this EU decision a deal breaker and unacceptable. My pointed question to the hon. Minister, through you, is that EU has started a trade war. Will the Civil Aviation Minister stop European airlines flying over India and let them go over Indian Ocean and the Bay of Bengal? What is the Civil Aviation Ministry's position in the ongoing talks in ICAO?

SHRI AJIT SINGH: This thing is being discussed at the ICAO and India has taken the lead to discussing this with many leading aviation countries on how to deal with this European Trade Emission law. We have instructed our airlines not to give any data to the European Union about their requirements for tags, emission and all that.